भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2772
मंगलवार 25 मार्च, 2025
4 चैत्र, 1947 (शक)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश में तेजी लाना

2772. **डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) इस विनिवेश से कितनी धनराशि मिलने की उम्मीद है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएसयू के विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार (i) अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और (ii) सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश करती है। सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना सेबी द्वारा अनुमोदित विभिन्न पद्धतियों जैसे कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापसखरीद आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से मूल्य को निर्मुक्त करने, जन स्वामित्व को बढ़ावा देने, सेबी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को पूरा करने और उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। रणनीतिक विनिवेश का आशय प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सीपीएसई में सरकारी शेयरधारिता के समग्र या पर्याप्त हिस्से की बिक्री से है।

वर्ष 2014-15 से, विभिन्न पद्धतियों/लिखतों का उपयोग करके विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 4,37,442 करोड़ रुपये (दिनांक 18.03.2025 की स्थिति के अनुसार) की धनराशि जुटाई गई। इसमें अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त 3,30,049 करोड़ रुपये, और 11 सीपीएसई में (एयर इंडिया,एनआईएनएल और एफएसएनएल का निजीकरण कर दिया गया है और शेष 8 सीपीएसई में रणनीतिक विनिवेश सीपीएसई से सीपीएसई क्षेत्र में किया गया था) रणनीतिक विनिवेश सौदों से 69,412 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त धनराशि (69,412 करोड़ रुपये) में एनआईएनएल और एफएसएनएल (सहायक कंपनी) के उद्यम मूल्य के रूप में क्रमश: प्राप्त 12,100 करोड़ रुपये और 320 करोड़ रूपए शामिल नहीं हैं चूंकि भारत सरकार की इन कंपनियों में कोई प्रत्यक्ष इक्विटी नहीं है। अन्य सौदों से 37,981 करोड़ रुपये का अर्थागम हुआ।

सरकार ने कंपनियों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा देने, सीपीएसई शेयरों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करने और उनके कार्यनिष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करने के उद्देश्य से गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के सूचीकरण की नीति को सक्रिय रूप से अपनाया है। 2014-15 से, 18 सीपीएसई (एलआईसीआई सहित) सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनसे 51,225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। नए सूचीकरण के माध्यम से 7.31 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बाजार पूंजीकरण (सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर गणित बाजार पूंजीकरण) हासिल किया गया। सूचिकरण के बाद, विभिन्न सीपीएसई में ओएफएस तंत्र द्वारा फिर विनिवेश से 1,34,771 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और 45 सीपीएसई द्वारा शेयरों की वापसखरीद से 45,104 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां हासिल हुईं।

रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को 2019 में संशोधित किया गया था ताकि प्रक्रिया को परिणामोन्मुखी और त्वरित बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("पीएसई") नीति को 27 जनवरी 2021 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 4 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति को कम करना है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री दोनों) करने या उनकी किन्ही भी सहायक कंपनियों या इकाईयों को बंद करने या संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सौदों की अनुशंसा करने और उसे शुरू करने का अधिकार है।

वर्तमान में, समग्र सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीति के एक भाग के रूप में, सरकार ने कंपनियों के सूचीकरण/आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और अल्पांश शेयरधारकों के हितों के अनुरूप शेयर बाजार के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करके एक अंशशोधित (कैलिब्रेटेड) विनिवेश रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अंशशोधित (कैलिब्रेटेड) रणनीति ने सीपीएसई को अपनी दक्षता और विकास में सुधार करने और पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण सहभागी बनने में सक्षम बनाया है। अंशशोधित विनिवेश दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित करता है कि जब भी सौदे किए जाएं, तो समग्र बाजार दिशा के अनुरूप बने रहें। इससे सीपीएसई के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिससे शेयरधारकों की प्राप्तियां बढ़ी हैं।

(ख) एवं (ग): विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और विशिष्ट सौदों का कार्यान्वयन/संपन्न होना प्रशासनिक व्यवहार्यता, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, भू-राजनैतिक कारकों, बाजार परिस्थितियों और निवेशक अभिरुचि पर निर्भर करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, किसी विशेष अवधि के लिए विनिवेश से वास्तविक प्राप्तियों की मात्रा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से वास्तविक विनिवेश प्राप्तियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**वास्तविक विनिवेश प्राप्तियां (करोड़ रुपए में)**
2021-22	13,534
2022-23	35,294
2023-24	16,507

*****